के. थुलासीधरन

बनाम

केरल राज्य सार्वजनिक सेवा आयोग, त्रिवेंद्रम और अन्य

30 अप्रैल, 2007

[सी. के. ठाकर और पी. के. बालासुब्रमण्यन, जे. जे.]

सेवा कानूनः

केरल लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम; नियम 13 परंतुक 5 ओवरसीयर ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्ति-श्रेणीबद्ध सूची-का विस्तार लोक सेवा आयोग द्वारा नियम 13 के 5 वें परंतुक के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए समय समाप्त सूची की वैधता का प्रयोग केवल एक मामले में किया जा सकता है-श्रेणीबद्ध सूची जो अस्तित्व में है और इसका उपयोग समय समाप्त सूची को फिर से मान्य करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

इन अपीलों में निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठा था, वह यह था कि केरल लोक सेवा आयोग के प्रक्रिया नियमों के नियम 13 के 5 वें प्रवधान के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए लोक सेवा आयोग, इसकी समाप्ति के बाद रैंक सूची की वैधता को बढा सकता है।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि लोक सेवा आयोग द्वारा इस मामले में अपनाया गया रुख कि उसके पास समाप्त हो चुकी श्रेणीबद्ध सूची की वैधता बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है, सही नहीं था और इसके साथ असंगत था अन्य मामलों में अपना पक्ष रखता है; और यह कि आयोग केवल अपीलार्थी के दावे को विफल करने के लिए एक असंगत रुख अपनाने के लिए खुला नहीं था।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित किया-

1.1. केरल लोक सेवा आयोग के प्रक्रिया नियमों के नियम 13 का परंतुक स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि इसके तहत उपलब्ध शक्ति का उपयोग केवल उस श्रेणीबद्ध सूची के मामले में किया जा सकता है जो अभी भी मौजूद है या जिसका जीवन अभी भी जारी है।

आयोग के पास उन श्रेणीबद्ध सूचियों को जीवित रखने की शक्ति होगी जो आम तौर पर उक्त अवधि के दौरान समाप्त होने वाली हैं" शब्द स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि यह एक जीवित सूची को भविष्य की तारीख तक जीवित रखने का सवाल है, जिसकी अवधि जल्द ही समाप्त होने वाली है। नियम 13 के उक्त परंतुक 5 के तहत शक्ति का उपयोग उस समय समाप्त हो चुकी श्रेणी सूची को पुनः मान्य करने के लिए नहीं किया जा सकता है। [पैरा 10]

1.2. उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है अदालत ने तब से जब तक सूचियों की वैधता बढ़ाने की अधिसूचना जारी की थी जारी की गई, प्रश्नगत सूची की वैधता समाप्त हो गई थी और वही नियमों के नियम 13 के 5वें परंतुक के तहत शक्ति के कथित प्रयोग में पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। [पैरा 10] [1046-ई-एफ]

न्यायालय ने कहा कि लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उससे अपेक्षा कि जाती है कि वह समतापुर्वक रूप से और सख्ती से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है कानून के अनुसार। जब नियमों के नियम 13 का पाँचवाँ प्रावधान उसे केवल सूचियों की वैधता को उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए बढ़ाने की शक्ति देता है उसमें दर्शाई गई परिस्थितियों में, इसके पास केवल एक रैंक वाली सूची को जीवित रहने की शक्ति है जो अभी चालु है जिस दिन निर्णय लिया जाता है और उस रैंक वाली सूची को पुर्नजीवित और जीवित नहीं रखा जाता है जो पहले समाप्त हो चुकी है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 2258/2007

केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम के 2004 के डब्ल्यू. ए. सं. 1341 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 02.08.2004 से।

के साथ

सिविल अपील सं. 2259-2260/2007

अपीलार्थी की ओर से सी. एस. राजन, ए. रघुनाथ और सी. के. सासी।

विपिन नायर, पी. बी. सुरेश, (टेम्पल लॉ फर्म के लिए), जी. प्रकाश, बीना प्रकाश और उत्तरदाताओं के लिए एम. टी. जॉर्ज।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

पी. के. बालासुब्रमण्यन, जे.

1. अनुमति दे दी गई।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी।

3. इस अपील में अपीलार्थियों को लोक निर्माण और सिंचाई विभागों में पर्यवेक्षक ग्रेड-II के पद पर नियुक्ति के लिए एक रैंक सूची में शामिल किया गया था। रैंक सूची 31.3.2001 पर प्रकाशित की गई थी। इसकी सामान्य वैधता एक वर्ष थी। लेकिन यदि कोई नई सूची तैयार नहीं की गई, तो इसकी वैधता तीन साल तक बढ़ा दी गई। कोई नई सूची तैयार नहीं की गई। इसलिए, सूची 31.3.2004 तक क्रियाशील थी।

4. तैयार की गई सूची में डिप्लोमा धारकों को इस आधार पर शामिल नहीं किया गया था कि उनके पास आवश्यक योग्यता से अधिक योग्यता थी। डिप्लोमा धारकों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कर केरल लोक सेवा आयोग को उन्हें रैंक सूची में शामिल करने का निर्देश

देने वाला एक आदेश पत्र जारी करने की मांग की। 18.2.2003 पर, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को अनुमति दी और निर्देश दिया कि डिप्लोमा धारकों सहित रैंक सूची को फिर से तैयार किया जाए। यह 31.3.2001 पर तैयार सूची के संचालन में कुछ देरी हुई।

5. उससे पहले भी, केरल सरकार ने राज्य में सेवाओं में मौजुदा परिस्थितियों को देखते हुए नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था । नई नियुक्तियों पर यह प्रतिबंध मई 2002 से नवंबर 2003 तक, 18 महीने की अवधि के लिए लागु था । परिणाम यह हुआ कि रिक्तियों की सूचना पर नियुक्ति के लिए केवल 633 नामों की अनुशंषा की गई थी।

6. केरल लोक सेवा आयोग के प्रक्रिया नियमों के नियम 13 के तहत, लोक सेवा आयोग के पास 5 वें प्रावधान के तहत, रैंक सूची को जीवित रखने की शक्ति थी, जो आम तौर पर उस अवधि के दौरान समाप्त होने वाली थी, जब नियुक्तियों पर प्रतिबंध था, प्रतिबंध की समाप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के लिए। 4.9.2002 को, नियमों के नियम 13 के 5 वें प्रावधान में संशोधन किया गया था। नियमों के नियम 13 के प्रतिस्थापित 5 वें परंतुक का इस प्रकार हैः

"बशर्ते कि यदि लोक सेवा आयोग को रिक्तियों की रिर्पोटिंग पर सरकार द्वारा घोषित सामान्य प्रतिबंध की अवधि के अस्तित्व

या किसी अन्य परिस्थिति से संतुष्ट है जिसमें नियुक्तिकर्ता द्वारा रिक्तियों को रोका या प्रतिबंधित किया जाता है, तो आयोग के पास रैंक सुचियों को जीवित रखने की शक्ति होगी जो आम तौर पर उक्त अवधि के दौरान समाप्त होने वाली हैं ऐसी अवधियों के लिए जो आयोग द्वारा तय की जा सकती हैं -तीन महीने की न्यूनतम अवधि या ऐसी आगे की अवधि के लिए लेकिन कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक नहीं। यदि आयोग ऐसा निर्णय लेता है तो वह उपरोक्त तरीके से रैंक की सूचियों को जीवित रखते हुए एक अधिसूचना जारी करेगा। और ऐसी श्रेणीबद्ध सूचियों से उम्मीदवारों को सलाह देगा वैधता की ऐसी विस्तारित अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई रिक्तियां के लिए ऐसी रैंक वाली सुचियों के उम्मीदवारों को सलाह देगा।"

7. 19.11.2003 को, केरल सरकार ने लोक सेवा आयोग को लागू प्रतिबंध को देखते हुए सूचियों की वैधता वर्ष 2004 के अंत तक बढ़ाने की सिफारिश की। लोक सेवा आयोग ने विस्तार करने के लिए नियमों के नियम 13 के 5 वें परंतुक के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया।

सूची की वैधता के लिए सरकार ने 21.2.2004 को फिर से लिखा। और लोक सेवा आयोग से दिसंबर 2004 के अंत तक रैंक की सूचियों को जीवित रखने के लिए कहा। इस अनुरोध के अनुसार, केरल लोक सेवा

आयोग ने 2.4.2004 पर बैठक की और मौजुदा सूचियों का विस्तार किया जो वर्तमान थीं और जो इसके बाद 30.12.2004 तक समाप्त होना था। द्वितीय श्रेणी पर्यवेक्षक से हमारा संबंध है उसके संबंध में श्रेणी की सूची, इस आधार पर जीवित नहीं रखा गया था कि सूची 31.3.2004 और 2.4.2004 को समाप्त हो गई थी, लोक सेवा आयोग उस सूची को जीवित रखने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सका जो पहले से ही समाप्त हो ग थीस प्रकार, हालांकि विस्तार से कुछ अन्य रैंक वाली सूचियों को लाभ हुआ, लेकिन विचाराधीन रैंक वाली सूची को 31.3.2004 द्वारा समाप्त माना गया।

8. उस संदर्भ में, अपीलार्थी ने एक रिट याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 2004 के डब्ल्यू. ए. संख्या 1053 में एक डिवीजन बेंच के फैसले के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह विचार रखा कि 3.4.2004 को जीवित रैंक वाली सुचियों की वैधता को बढाने के लिए लेक सेवा आयोग को निर्णय नहीं किया जा सकता। इस दावे पर भरोसा किया गया कि संबंधित रैंक सुची जो 31.3.2004 तक समाप्त हो गई थी, उसे पुनर्जीवित कर दिया गया था या जीवित रखा गया था। यह तर्क कि यदि लोक सेवा आयोग ने त्वरित कार्रवाई की होती, तो संबंधित रैंक सूची की वैधता भी बढ़ जाती, कानूनी स्थिति के आलोक में खारिज कर दी गई। इसके बाद अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ

के समक्ष अपील दायर की। डिवीजन बेंच ने 2004 के डब्ल्यू. ए. नंबर 1053 में अपने पूर्व निर्णय का उल्लेख करने के बाद और इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि संबंधित सूची विभिन्न सूचियों की वैधता बढ़ाने की अधिसूचना जारी होने से पहले समाप्त हो गई थी, यह माना गया कि समाप्त हो चुकी सूची को शक्ति के प्रयोग में जीवित नहीं रखा जा सकता है या पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। नियमों के नियम 13 का परन्तुक 5 प्रावधान। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि करते हुए, अपील को खारिज कर दिया गया। डिवीजन बेंच के निर्णय को अपीलार्थी और कुछ अन्य समान रूप से स्थित लोगों के कहने पर हमारे सामने चुनौती दी गई है।

9. अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सी. एस. राजन यह इंगित किया कि लोक सेवा आयोग द्वारा इस मामले में अपनाया गया रुख कि आयोग के पास समाप्त हो चुकी रैंक सूची की वैधता बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है, सही नहीं था और अन्य मामलों में अपने स्वयं के रुख से असंगत था। विद्वान वकील ने दो अन्य उदाहरणों की ओर इशारा किया जहां आयोग ने सूचियों की वैधता बढ़ा दी थी, जिसकी अवधि नियमों के नियम 13 के 5वें परंतुक के तहत शक्ति के प्रयोग में अधिसूचना जारी होने के दिन पहले समाप्त हो गई और तर्क दिया कि केवल अपीलार्थी के दावे को विफल करने के लिए लोक सेवा आयोग असंगत रुख अपनाने के

लिए तैयार नहीं है। लोक सेवा के लिए विद्वान वकील आयोग वास्तव में यह नहीं बता सके कि अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा बताए गए मामलों में लोक सेवा आयोग उन सुचियों को कैसे पुनः मान्य कर सकता था जो पहले ही समाप्त हो चुकी थीं। हालांकि, परिस्थितियों पर विचार करते हुए, हम अपीलार्थियों को कोई राहत देना संभव नहीं हैं क्योंकि संबंधित नियम की व्याख्या पर, हम 2004 की डब्ल्यू. ए. संख्या 1053 में निर्णय और अपील के तहत निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से असहमत होने की स्थिति में नहीं हैं।

10. नियमों के नियम 13 का पाँचवाँ प्रावधान स्पष्ट रूप से देता है कि इसके तहत उपलब्ध शक्ति का उपयोग केवल उस रैंक वाली सूची के मामले में किया जा सकता है जो अभी भी मौजूद है या जिसका जीवन अभी भी जारी है। शब्द "आयोग के पास उन रैंक की सूचियों को जीवित रखने की शक्ति होगी जो आम तौर पर उक्त अवधि के दौरान समाप्त होने वाली हैं" (जोर दिया गया) स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह एक जीवित सूची को भविष्य की तारीख तक जीवित रखने का सवाल है, जिसकी अवधि जल्द ही समाप्त होने वाली है। नियमों के नियम 13 के 5वें प्रावधान के तहत समय समाप्त हो चुकी श्रेणी सूची को फिर से मान्य करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा बताए गए दो उदाहरण जहां लोक सेवा

आयोग ने ऐसा किया था, नियमों के नियम 13 के 5वें परंतुक के आलोक में कानूनी रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्हें विचलन के रूप में माना जाना चाहिए। वे किसी भी अधिकार की नींव नहीं बना सकते। इस स्थिति में, हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि 03-04-2004 तक जब सूचियों की वैधता बढ़ाने की अधिसूचना जारी की गई थी, तो विचाराधीन सूची की वैधता समाप्त हो गई थी और इसे नियम 13 के 5वें परंतुक के तहत शक्ति के कथित प्रयोग में पुनर्जीवित नहीं किया जा सका था।

11. मामले से अलग होने से पहले, हम सोचते हैं कि लोक सेवा आयोग के असंगत आचरण पर अपनी नाखुशी व्यक्त करना आवश्यक है। लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है और यह अपेक्षा कि जाती है कानून के अनुसार समान रूप से और सख्ती से कार्य करें। जब नियमों के नियम 13 का 5वां परंतुक उसे केवल सूचियों की वैधता को उसमें निर्दिष्ट परिस्थितियों में उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए बढ़ाने की शक्ति देता है, तो उसके पास केवल एक रैंक वाली सूची को जीवित रखने की शक्ति है जो अभी भी मौजूद है जिस दिन निर्णय लिया गया था और उस रैंक वाली सूची को पुनर्जीवित करने और जीवित रखने की शक्ति नहीं है जो पहले ही समाप्त हो चुकी थी। स्वयं लोक सेवा आयोग का जवाबी हलफनामा यह इंगित करता है कि उच्च न्यायालय ने लगभग 50 मामलों में ऐसा

दृष्टिकोण अपनाया है। लोक सेवा आयोग जैसे संवैधानिक निकाय से ऐसे आदेश या अधिसूचना जारी करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जिसके लिए उसके पास कोई अधिकार नहीं है।

एक सही व संबंधित प्रावधान का निर्माण यह स्थिति है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष और हमारे समक्ष वर्तमान मामले में अपनाया गया रुख यह भी है कि नियमों के नियम 13 के 5वें के प्रावधान के अनुसार इसके पास मृत सूची को पुनर्जीवित करने की कोई शक्ति नहीं है और यह केवल एक सूची को आगे की अवधि के लिए जीवित रखना है जो निर्णय लेने के दिन भी जीवित रहती है। हमें विश्वास है कि लोक सेवा आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए आदेश जारी करने जैसी अवैधताएं, लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गई सूचियों में शामिल कई में से कुछ के लिए कठिनाई और पीड़ा पैदा नहीं कर हैं।

12. चूंकि हम उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत हैं, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। हम अपील को खारिज करते हैं।

पी. के. बालासुब्रमण्यन, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी।

3. अपीलार्थी को केरल राज्य विद्युत बोर्ड में नियुक्ति के लिए लोअर डिवीजन क्लर्कों की श्रेणीबद्ध सूची में शामिल किया गया था। सूची 24.1.2001 पर प्रकाशित की गई थी और तीन साल की समाप्ति पर, यह 24.01.2004 पर समाप्त होने वाली थी। 19.11.2003 पर, केरल लोक सेवा आयोग ने सूची की वैधता 4.2.2004 तक बढ़ा दी। इसके बाद सूची समाप्त हो गई। रैंक संख्या 133 रखने वाले अपीलार्थी को नियुक्ति के लिए सलाह नहीं दी गई थी और केवल 60 तक के रैंक वाले लोगों को सूची से नियुक्ति के लिए सलाह दी गई थी, जब तक कि वह जीवित था। यह उस स्थिति में था जब अपीलार्थी ने लोक सेवा आयोग और केरल राज्य विद्युत बोर्ड को नियुक्ति के लिए सलाह देने और सूची की वैधता बढ़ाने के बाद उसे नियुक्ति देने का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

4. रिट याचिका और उससे अपील को इसके बाद खारिज कर दिया गया था निर्णय जिसने उस अपील को जन्म दिया है जिसका हमने 2004 की अपील के लिए विशेष अनुमति (सिविल) संख्या 21495 और 2005 की संख्या 261 के लिए याचिकाओं से उत्पन्न होकर आज अलग से दिए गए निर्णय द्वारा निपटारा किया है।

5. उस निर्णय में हमने जो दृष्टिकोण लिया है, सूची समाप्त हो गई है 04-02-2004 द्वारा, और इसके बाद इसकी वैधता को नहीं बढ़ाया गया

है, उच्च न्यायालय में जमीन पर अपीलार्थी को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। लेकिन, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने हमारे सामने एक नया विवाद उठाया, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया नहीं देखा जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि 19.11.2003 पर, लोक सेवा आयोग ने का विस्तार करने का निर्णय लिया।

सूची की वैधता 4.2.2004 तक बढ़ायी, जो 24.1.2004 द्वारा समाप्त होने वाली थी। इसका मतलब यह था कि सूची को जीवित रखने की शक्ति का प्रयोग समय पर किया गया था, लेकिन इसका उपयोग ठीक से नहीं किया गया था क्योंकि इसे 5वें के संदर्भ में विस्तारित नहीं किया गया था। नियमों के नियम 13 का प्रावधान। विद्वान वकील ने बताया कि नियमों के नियम 13 के 5वें प्रावधान के तहत, आयोग के पास रखने की शक्ति थी श्रेणीबद्ध सूची जो आयोग द्वारा तय की गई ऐसी अवधि के लिए समाप्त होने वाली थी, न्यूनतम तीन महीने की अवधि के अधीन या ऐसी आगे की अवधि के लिए लेकिन कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक नहीं वकील ने बताया कि 19.11.2003 पर, आयोग ने जो किया वह सूची के जीवन को केवल 11 दिनों तक बढ़ाना था और यह सूची को तीन महीने से कम नहीं बल्कि एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जीवित रखने की उनकी शक्ति के अनुरूप नहीं था। इसलिए, यह लिया जाना चाहिए कि

19.11.2003 पर, सूची को कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए जीवित रखने का निर्णय लिया गया था।

6. लोक सेवा आयोग के विद्वान वकील सूची की वैधता को न्यूनतम तीन महीने की अवधि के लिए ब़ढाने के बजाय केवल 11 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाने का कारण नहीं दे सके, लेकिन विद्वान वकील ने कहा कि इस तरह का विवाद नहीं उठाया गया था और इसलिए वह परिस्थितियों को समझाने की स्थिति में नहीं थे। यद्यपि हम अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए जाने की मांग किए गए विवाद में कुछ बल देखते हैं क्योंकि हम पाते हैं कि सूची की वैधता को 4.2.2004 से नहीं बढ़ाया गया था और तीन साल बीत चुके हैं, हमारे सामने उठाई जाने वाली नई याचिका के आधार पर, रिट याचिका में अपीलार्थी को कोई राहत देने के लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा, भले ही यह अन्यथा संभव हो। इस स्थिति में हम उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं और अपील को खारिज करते हैं।

एसकेएस.

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजीव जांगिड़ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।